शिक्षा का अधिकार एवं केन्द्रीय बजट

(2016-17)

नेसार अहमद

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केन्द्रीय बजट 2016-17 पेश करते हुए कहा कि भारत सरकार के लिये ''अब शिक्षा की गुणवत्ता अगला बड़ा कदम होने वाला है।'' परन्तु इस बजट में शिक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए आंवटन में ऐसी कोई प्राथमिकता दिखाई नहीं पड़ी। विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता विभाग का कुल बजट 2016-17 के लिए 43554 करोड़ रुपये रखा गया है जो वर्ष 2015-16 (संशोधित अनुमान) से मात्र 3.24 प्रतिशत अधिक है तथा वर्ष 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान हुए आंवटन से कम ही है। यही नहीं भारत सरकार के कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का बजट वर्ष 2012-13 के 4.7 प्रतिशत से घट कर 2016-17 में 3.7 प्रतिशत रह गया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का बजट (करोड़ रुपये)

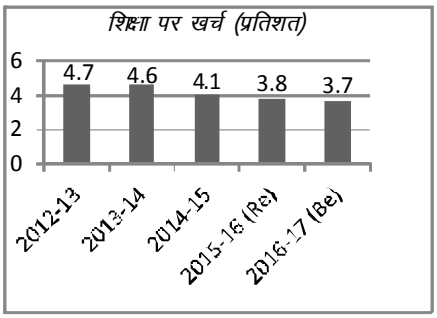

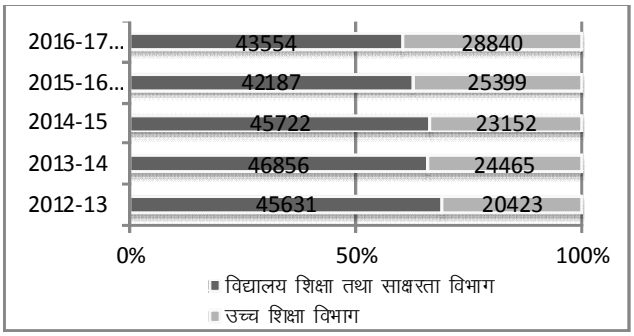

शिक्षा का अधिकार एवं बजट

देश में शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान मुख्य योजना है। इस योजना के लिए किए गए आंवटन में पिछले वर्ष की अपेक्षा मात्र 2.2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस वर्ष (2016-17) भारत सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान के लिए 22,500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं जो पिछले वर्ष 2015-16 (संशोधित अनुमान) में 22,015 करोड़ रुपये था। अब बदले हुए पैटर्न में सर्वशिक्षा अभियान में केन्द्र का हिस्सा 60 प्रतिशत है तथा 40 प्रतिशत हिस्सा राज्यों (पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों को छोड़कर) को देना होगा। लेकिन उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि देश के मात्र 8 प्रतिशत स्कूल शिक्षा के अधिकार कानून के मानदंडों पर खरे उतरते हैं। ऐसे में इस छोटे से बजट से शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना मुश्किल है।

शिक्षा के क्षेत्र में चुनिंदा योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन (रुपये करोड़ में)

योजनाएं	2014-15	2015-16(BE)	2015-16(RE)	2016-17(BE)
सर्व शिक्षा अभियान	24,097	22,000	22,015	22,500
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	3,398	3,565	3,565	3,700
शिक्षक प्रशिक्षण और साक्षर भारत	1,158	1,397	1,203	879
मदरसा और अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना	119	376	336	120
केन्द्रीय विद्यालय संगठन	3,243	3,278	3,278	3,795
नवोदय विद्यालय संगठन	2,013	2,061	2,285	2,471
मिड डे मिल	10,523	9,236	9,236	9,700

जहां तक गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा का सवाल है, जिसे वित्त मंत्री ने आने वाले वर्षों में सरकार का मुख्य कदम बताया है, उसके लिए भी राज्य सरकारें मुख्य रूप से सर्वशिक्षा अभियान पर ही निर्भर हैं। भारत सरकार के बजट में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए वर्ष 2016-17 में 510 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जो वर्ष 2015-16 में 558 करोड़ रुपये था।

बालिका शिक्षा

पिछले दो वर्षों में सरकार ने बालिकाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रगति, उड़ान, अकेली बच्ची के लिए स्वामी विवेकानन्द छात्रवृत्ती आदि की घोषणा की है। लेकिन इस बजट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए 100 करोड़ रुपये छोड़कर किसी भी अन्य योजना के लिये स्पष्ट आंवटन नहीं किया गया है।

प्राथमिक शिक्षा के लिए भारत सरकार की अन्य योजनाएं

इस बजट में वित्त मंत्री ने 62 नए नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव भी रखा है, किन्तु नवोदय विद्यालय संगठन के बजट में मात्र 200 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। जबकि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के बजट में करीब 500 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। मध्याह्न भोजन योजना के बजट में भी 500 करोड़ रुपये से कम की बढ़ोतरी हुई है तथा 2016-17 का मध्याह्न भोजन योजना का कुल बजट वर्ष 2014-15 से कम रखा गया है।

कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि भारत सरकार प्राथमिक शिक्षा का अधिकतर भार राज्य सरकारों के कंधों पर डालना चाहती है। ऐसा चौदहवें वित्त आयोग के बाद केन्द्रीय करों में राज्य सरकारों के बढ़े हिस्से के मद्देनजर किया जा रहा है। परन्तु हम जानते हैं कि इसके साथ ही केन्द्र सरकार ने राज्यों को दिए जा रहे अनुदान तथा अन्य सहायता में कटौती भी कर दी है। ऐसे में राज्य सरकारें शिक्षा के अधिकार को पूरी तरह से लागू करने में सक्षम होती हैं या नहीं यह एक गंभीर प्रश्न है। ◆

संदर्भः सभी आंकड़े सीबीजीए, नई दिल्ली के प्रकाशन कन्नेक्टिंग द डॉट्स एन एनालिसिस ऑफ यूनियन बजट 2016-17 से लिए गए हैं।

लेखक परिचयः जयपुर स्थित बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र (बार्क) के समन्वयक हैं।